हिन्द – प्रशांत के लिए आसियान नीति

10-07-2019

MPPSC UPSC

MPSI IAS IPS

चर्चा में क्यों:

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान (Association of Southeast Asian Nations) का 34 वाँ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिये आसियान की नीति स्पष्ट की गई। इस संगठन के सदस्यों ने सामूहिक रूप से एक विज़न दस्तावेज़ - द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक जारी किया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र :- हिंद-प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीति एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। साथ ही यह क्षेत्र अपनी अवस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है, तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल हैं। विश्व GDP के 60% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापार (पेट्रोलियम उत्पाद) को लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों राष्ट्रों के लिये संवेदनशील बना रहता है।

क्या है, आसियान-

- आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी।
- वर्तमान में 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है।

- भारत और आसियान देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब के लक्ष्य तक ले जाने के लिये जूझ रहे हैं।
- इसके लिये अन्य बातों के साथ-साथ स्थल, समुद्र और वायु कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि माल और सेवाओं के आवागमन की लागत में कटौती की जा सके।

आसियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- अंतरक्षेत्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अनुपूरक संबंध।
- सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों का विकास।
- पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना।
- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।

भारत एवं आसियान-

आसियान का यह विज़न दस्तावेज़ एक जैसे विचार रखने वाले देशों को सहयोग के माध्यम से जुड़ने पर भी ज़ोर देता है। भारत पहले से ही मुक्त, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की नीति पर बल देता रहा है इसलिये इस क्षेत्र हेतु आसियान की नीति का भारत द्वारा समर्थन किया जाना स्वाभाविक है। भारत और आसियान के मध्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें कार्य करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है जैसे- IORA (Indian Ocean Rim Association), BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), मेकॉंग सहयोग फ्रेमवर्क आदि।

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station, Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

कैश-लेस या लेस-कैश अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों: नकदी रहित यानी कैश-लेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले कारोबारी कम लागत वाले डिजिटल तरीके से भुगतान की पेशकश कर सकते हैं और इसके लिये उन पर या उनके ग्राहकों पर कोई शुल्क या मर्चेंड डिस्कांउट नहीं लगाया जाएगा। नकद व्यावसायिक भुगतान करने की परिपाटी को हतोत्साहित करने के लिये एक वर्ष में एक बैंक खाते से एक करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी के मामले में स्त्रोत पर 2% TDS लगाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने बजट में किया है। लोगों द्वारा भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने की वजह से इन पर आने वाले खर्च को भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य बैंक उस बचत से वहन करेंगे जो उनको कम नकदी संभालने के कारण होगी।

बढ़ रहा है कैश-लेस लेनदेन का चलन - मोबाइल फोन आधारित भुगतान का इस्तेमाल करने से डिजिटल लेनदेन की संख्या भी बढ़ी है। जून 2019 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface UPI) लेनदेन 754 मिलियन रुपए तक पहुँच गया है। तुरंत भुगतान सेवा (Immediate Payment Seeice - IMPS) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (Natinal Payment Corporation India NPCI) से होने वाला लेनदेन क्रमशः 171 मिलियन और 26 मिलियन रहा।

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station,
Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

कैश-लेस अर्थव्यवस्था क्या है ?- नकदी-रहित लेनदेन में करेंसी का न्यूनतम इस्तेमाल होता है। इससे व्यवसाय स्वचालित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कालेधन का प्रभाव कम होता है। आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेनदेन चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है, कैश-लेस अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में नकदी (कागजों नोट या सिक्के) का चलन कम हो जाता है।

वर्तमान में देश का लगभग 95% लेनदेन नकद- आधारित है जिससे एक बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और इसकी वजह से सरकार को विभिन्न टैक्स लगाने और वसूलने में कठिनाई होती है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न उपायों की घोषणा करती रहती है।

KAUTILYA ACADEMY
INDORE

By- Pankaj Bodiya

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station,
Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001